



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2018/चैत्र 21, 1940

No. 132]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2018/CHAITRA 21, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2018

सं. ओ-31018/149/2016-ओएनजी.III.—सरकार ने तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन ईएंडपी क्षेत्र में प्रमुख सुधार शुरू किए हैं। नामांकन व्यवस्था के तहत आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लि. (ओआईएल) के लंबी अवधि तक विकसित नहीं किए गए सीमांत क्षेत्रों से मुद्रा अर्जित करने के लिए दिनांक 14 अक्तूबर, 2015 को सीमांत क्षेत्र नीति (एमएफपी) अधिसूचित की गई थी। बाद में, इस नीति का नाम बदलकर खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति कर दिया गया था जो अब देश की फ्लैगशिप ऊर्जा नीतियों में से एक है, जो देश की ऊर्जा जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए अन्य पहलों के अनुरूप है।

सरकार ने नामांकन व्यवस्था के तहत ओएनजीसी और ओआईएल के गैर मौद्रिक लघु क्षेत्रों/खोजों और पीएससी व्यवस्था के तहत गैर-मौद्रिक परित्यक्त खोजों का तेजी से मौद्रिकरण करने के लिए खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति को लागू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, डीएसएफ नीति को अब निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं के साथ अधिसूचित किया जा रहा है।

2. परंपरागत और गैर-परंपरागत हाइड्रोकार्बनों के लिए एकल लाइसेंस

ईएंडपी प्रचालकों को एकल लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे तेल क्षेत्र विनियम और विकास (ओआरडी) अधिनियम, 1948 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नियम, 1959 के तहत कवर किए गए सभी हाइड्रोकार्बन संसाधनों का अन्वेषण और निष्कर्षण एक पीईएल/पीएमएल के अंतर्गत करने में समर्थ हो सके। इससे संविदाकार सीबीएम, शेल गैस/तेल, टाइट गैस, गैस हाइड्रेट्स और भविष्य में खोजे जाने वाले अन्य संसाधन, जो पीएनजी नियम, 1959 के तहत “पेट्रोलियम” और “प्राकृतिक गैस” की परिभाषा में आते हों, सहित परंपरागत और गैर-परंपरागत तेल और गैस संसाधनों का अन्वेषण करने में समर्थ होंगे।

3. संविदा अवधि के दौरान अन्वेषण कार्यकलाप पर कोई प्रतिबंध नहीं

संविदाकार को पूरी संविदा अवधि के दौरान अन्वेषण कार्यकलाप करने की अनुमति दी जाएगी। अन्वेषण कार्य संविदाकारों के एक मात्र जोखिम और लागत पर किया जाएगा।

4. बोलिया आमंत्रित करने के लिए मॉडल

सीमांत क्षेत्रों के लिए बोलियां राजस्व हिस्सेदारी संविदा (आरएससी) मॉडल के आधार पर आमंत्रित की जाएंगी। प्रचालनों की साध्यता को सुनिश्चित करने के लिए, कलस्टर क्षेत्रों/खोजों, जैसा भी प्रस्ताव आमंत्रण नोटिस (एनआईओ) के समय अपेक्षित हो, का प्रस्ताव है। यह राजस्व हिस्सेदारी मॉडल एक राजस्व-आधारित लाइनियर स्केल पर आधारित होगा। संविदाकार द्वारा राजस्व के बोली योग्य सरकारी हिस्से (रायल्टी अथवा रायल्टी-उपरांत का निवल) का भुगतान किया जाना अपेक्षित होगा।

5. कारोबार को आसान बनाना

इन क्षेत्रों का मौद्रीकरण करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम विनियामक नियंत्रण के लिए 'व्यवसाय को सरल बनाने' को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयासों के अनुसार एक सहज और सरल प्रशासन वाला संविदागत मॉडल विकसित किया गया है।

6. कच्चा तेल मूल्य निर्धारण और बिक्री

संविदाकार आर्म्सलैथ आधार पर एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से विशेष रूप से घरेलू बाजार में कच्चे तेल की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तथापि, सरकार के राजस्व का परिकलन करने के उद्देश्य से, पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा मासिक आधार पर यथा परिकलित न्यूनतम मूल्य ही कच्चे तेल की भारतीय बास्केट [वर्तमान में इसमें भारतीय रिफाइनरियों में प्रसंस्कृत कच्चे तेल का शोर ग्रेड (ओमान और दुबई औसत) और स्वीट ग्रेड (ब्रेंट दिनांकित) शामिल हैं] का मूल्य होगा। यदि बोली के माध्यम से प्राप्त मूल्य कच्चे तेल की भारतीय बास्केट के मूल्य से अधिक होता है तो सरकार के हिस्से का परिकलन प्राप्त वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

7. प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण

संविदाकार को किसी कलस्टर/क्षेत्र/खोज से उत्पादित गैस का आर्म्सलैथ आधार पर मूल्य निर्धारण और आबंटन करने की स्वतंत्रता होगी। राजस्व के सरकारी हिस्से का परिकलन संबंधित समय पर प्रचलित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। तथापि, यदि प्राप्त मूल्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य दिशा निर्देशों के आधार पर परिकलन से अधिक होता है तो सरकार के हिस्से का परिकलन प्राप्त वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

8. रायल्टी

इस नीति में, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) व्यवस्था के तहत लागू रायल्टी दरों को अपनाया जाएगा।

9. तेल उपकर

खोजे गए लघु क्षेत्रों से कच्चे तेल/कंडेनसेट के उत्पादन पर कोई तेल उपकर लागू नहीं होगा।

10. सीमा शुल्क

एचईएलपी में यथा लागू पेट्रोलियम प्रचालनों से संबंधित सभी मशीनरी, संयंत्रों, उपकरणों, सामग्रियों और आपूर्तियों पर सीमा-शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी।

11. खनन

वर्तमान खनन पट्टा/लाइसेंस धारकों द्वारा क्षेत्र प्राप्तकर्ता/संविदाकार को कानूनी रूप से व्यवहार्य सीमा तक सभी उपलब्ध मंजूरीयों सहित खनन पट्टा (एमएल) अथवा पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) को अंतरित किया जाना/सौंपा जाना अपेक्षित होगा अथवा संविदाकार को इसे प्राप्त करना होगा। पट्टा/लाइसेंस किराए/शुल्कों को समय-समय पर यथा संशोधित ओआरडी अधिनियम 1948 और पीएंडएनजी नियम 1968 के अनुसार अभिशासित किया जाएगा।

12. संविदा अवधि

प्रस्तावित खोजे गए लघु क्षेत्रों के विकास और उत्पादन के लिए संविदा अवधि संविदा के लागू होने (प्रभावी तारीख पीईएल/एमएल प्रदान करने/अंतरण/ करार पर हस्ताक्षर की तारीख होती है) की तारीख से अधिकतम बीस (20) वर्ष अथवा बोलीदाता द्वारा विकास योजना के साथ यथा प्रस्तुत क्षेत्र के आर्थिक जीवनकाल तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी जब तक कि संविदा को इसकी शर्तों के अनुसार पहले ही समाप्त न कर दिया जाए, परंतु पक्षकारों के बीच परस्पर करार के आधार पर इसे आगे अधिकतम दस (10) वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। यदि कच्चे तेल अथवा प्राकृतिक गैस का उत्पादन उपर्युक्त उल्लिखित संगत अवधि के समाप्त होने के बाद भी जारी रहने की संभावना होती है तो पक्षकार परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर इस संविदा अवधि को अगली अवधि तक बढ़ाने के लिए सहमत हो सकते हैं। संविदा के प्रावधानों और मौजूदा जीओआई दिशा निर्देशों, यदि कोई हो, के आधार पर संविदा को बढ़ाया जा सकता है यदि प्रस्तुत किए गए खोजे गए लघु क्षेत्रों से उत्पादन किसी

भी परिस्थिति में एक (1) वर्ष से अधिक अवधि के लिए बंद रहता है तो जीओआई द्वारा संविदा को पहले ही समाप्त किया जा सकता है।

13. सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति:

सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएस) का गठन किया जाएगा जिसमें सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस), सचिव (व्यय) और विधि सचिव शामिल होंगे। ईसीएस के कार्यों में मॉडल राजस्व हिस्सेदारी संविदाओं, प्रस्ताव आमंत्रण नोटिस (एनआईओ) और सभी खोजे गए लघु क्षेत्र बोली दौरों के लिए अन्य दस्तावेज को अंतिम रूप देना और अनुमोदन करना शामिल होंगे। ईसीएस जरूरी होने पर बोलीदाताओं के साथ बातचीत करेगी और सफल बोली दौर के बाद संविदा क्षेत्रों के लिए संविदाओं को अंतिम रूप देगी और प्रदान करने की संस्तुति करेगी।

14. संविदाओं को प्रदान करने का अनुमोदन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा किया जाएगा।

15. प्रबंधन समिति

एक प्रबंधन समिति (एमसी) का गठन किया जाएगा जिसमें सरकार/हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) और संविदाकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

16. बोलियों में भाग लेने के लिए पात्रता

राष्ट्रीय तेल कंपनियां, भारतीय कंपनियां और विदेशी कंपनियां या तो अकेले अथवा संयुक्त उद्यम में प्रस्तावित खोजे गए लघु क्षेत्र के लिए बोली लगा सकती है। विदेशी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों द्वारा 100% तक भागीदारी की अनुमति दी जाएगी।

17. स्थल बहाली

अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित “स्थल बहाली निधि योजना-1999” के अनुसार संविदाकार द्वारा स्थल बहाली निधि अनुरक्षित की जाएगी। स्थल बहाली से संबंधित कार्यकलाप लागू नियमों/मानकों/अधिसूचनाओं के अनुसार किए जाएंगे।

18. उपर्युक्त डीएसएफ नीति को सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 60 चिह्नित क्षेत्रों/खोजों के लिए लागू किया गया है। चिह्नित क्षेत्रों/खोजों की सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

19. सरकार ने उपर्युक्त डीएसएफ नीति को भावी बोली दौरों के लिए आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। अपर सचिव/अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (एमओपीएनजी), संयुक्त सचिव (अन्वेषण, एमओपीएनजी) और हाइड्रोकार्बन महानिदेशक की एक समिति सीएमडी (ओएनजीसी) और सीएमडी (ओआईएल) के साथ परामर्श करके भावी बोली दौरों के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले क्षेत्रों/खोजों की पहचान करेगी।

20. इसमें निहित निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेशों तक लागू रहेंगे।

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

डीएसएफ नीति बोली दौर-II के लिए चिह्नित ओएनजीसी खोजें

क्रम सं.	बेसिन का नाम	खोज के ब्यौरे			दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार तत्स्थल भंडार	
		नाम	वर्ष	प्रकार	तेल कंटेनसेट / एमएमटी	कुल गैस, बीसीएम
1	असम शेल्फ	तिफुख	2004-05	तेल गैस +	0.40	0.11
2		तुलामुरा	2008-09	गैस	-	0.20
3		हजारीगांव	2008-09	गैस	-	0.30
4	केजी ऑफशोर (एसडब्ल्यू)	जी एस-48-1	2007-08	गैस	-	0.42
5		जी 4-6	2008-09	तेल	44.10	2.60
6		जी एस-69	2009-10	तेल गैस +	0.30	0.80
7		जी एसकेडब्ल्यू-5	2007-08	तेल	0.13	0.41
8		जी एस-केडब्ल्यू-6	2009-10	गैस	1.22	2.78
9	केजी जमीनी	काजा	1985-1986	गैस	0.02	0.01

क्रम सं.	बेसिन का नाम	खोज के ब्यौरे			दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार तत्स्थल भंडार	
		नाम	वर्ष	प्रकार	तेल कंटेनरसेट / एमएमटी	कुल गैस, बीसीएम
10		गोकरनपुरम	1998-1999	गैस	0.1	0.03
1 1		पेंडुरू	2001-02	गैस	-	0.12
12		तुरपुतुल्लू	2005-06	गैस	0.1	0.01
13		सूर्यपिटा -4	2006-07	गैस	-	0.2
14	मुंबई अपतटीय	एसडी -1	1988-1989	तेल गैस +	0.90	4.52
1 5		बी-192A	1991-1992	तेल	1.93	0.30
1 6		डी-33	2004-05	तेल गैस +	23.90	16.70
17		बीएनपी -2	2008-09	गैस	-	0.70
18		एस-बी.15	2008-10	तेल	4.62	2.19
19		एसडी-1-5	2009-10	तेल गैस +	0.70	2.43
2 0		बीएच-67	2011-12	गैस	-	0.24
2 1	राजस्थान	चिन्नेवाला टिब्बा	2007-08	गैस	-	1.90
2 2		चिन्नेवाला टिब्बा -2	2002-04			
कुल : (115.39 एमटीओई)					78.42	36.97

डीएसएफ नीति बोली दौर-II के लिए चिह्नित ओआईएल खोजें

क्रम सं.	बेसिन का नाम	नाम	वर्ष	तेल कंटेनर / (एमएमटी)	गैस(बीसीएम)
1	असम	दक्षिण राजगढ़	1994	1.48	-
2	असम	मध्वाकाली	2010	0.23	-
3	असम	उमातारा	2010	3.37	-
4	असम	हल्दीबाड़ी	2001	0.05	-
5	असम	दिसाईजान	2009	0.98	-
योग				6.11	-

डीएसएफ नीति बोली दौर-II के लिए चिह्नित पीसीएम व्यवस्था की खोजें

क्रम सं.	बेसिन	ब्लॉक का नाम	स्थिति	खोज का नाम	खोज का वर्ष	ब्लाक प्रचालक	तेल गैस/	प्रारंभिक तत्स्थान (ओ + ओईजी), एमएमटी
1	खंभात	सीबी / ओएस-1	पीएफआर	गल्फए-	2008-09	ओएनजीसी	तेल	4.98
2		सीबी- ओएनएन-2004 / 2		वेदताल-10	2014-15	ओएनजीसी	तेल	0.09
3				वेदताल-11	2014-15	ओएनजीसी	तेल	0.218
4		सीबी- ओएनएन-2009 / 5		एनटीपीसी ए-1	2016-17	एनटीपीसी	तेल	8.88
5		संगनपुर		संगनपुर	2006-07	एचडीसीपीएल	तेल	0.858
6		सीबी ओएनएन-2003-1		डी-45	2009-10	आरआईएल	गैस	0.008
7	महानदी	एनईसीओएसन--97/2	पीएफआर	डी -9	2004-05	आरआईएल	गैस	5.15
8		एनईसीओएसन - -97/2		डी-10	2004-05	आरआईएल	गैस	1.08
9		एनईसीओएसन - -97/2		डी-11	2004-05	आरआईएल	गैस	6.48

10		एनईसीओएसन - - 97/2		डी-15	2004-05	आरआईएल	गैस	1.78
11		एनईसीसनओए - - 97/2		डी-20	2005-06	आरआईएल	गैस	0.44
12		एनईसीओएसन - - 97/2		डी-21	2005-06	आरआईएल	गैस	1.61
योग								31.57

डीएसएफ नीति बोली दौर-II के लिए डीएसएफ बोली दौर 2016 की शेष खोजें

क्रम सं.	स्थल क्षेत्र	क्षेत्र	खोज का वर्ष	प्रारंभिक तत्स्थल	
				तेल	गैस (एसजी+ एफजी)
				एमएमटी	बीसीएम
1	मुंबई अपतटीय	एनएमटी	2003-04	-	5.49
2		प्रति	2010-11	2.14	0.93
3		बी-163	1990-1991	-	0.14
4		बी-14	2000-01	-	0.07
5		सी-37	1994-1995	-	1.33
6		सी-43	1995-1996	-	0.30
7		डी-18	1985-1986	14.78	2.06
8	मुंबई अपतटीय	सीए	1986-1987	1.93	3.51
9		एसडी -14	1989-1990	0.05	0.04
10		सीडी	1986-1987	-	0.07
11		प्रवर्तन निदेशालय -4	2000-01	0.03	-
12		एसडी-4	1988-1989	0.15	0.18
13		टी.पी.	1999-2000	-	0.33
14		डी-12	1981-1982	-	0.61
15		डी-31	2000-01	3.78	0.53
16	कच्छ अपतटीय	जी -39	2000-01	-	0.05
17	कृष्णा गोदावरी (अपतटीय)	जी एस-70	2011-12	0.4	0.45
18		वाईएस -5	2008-09	-	1.69
19	कृष्णा गोदावरी (जमीनी)	लंकाप्लेन	1995-1996	-	0.22
20		मुंमीदिवरम	1992-1993	-	0.09
21		पलाकोल्लू	1986-1987	-	0.23
योग (41.58एमटीओई)				23.26	18.32

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**RESOLUTION**

New Delhi, the 5th April, 2018

No. O-31018/149/2016-ONG.III.—Government has initiated key reforms in the Upstream Hydrocarbon E & P Sector to increase domestic production of oil and gas. Marginal Field Policy (MFP) was notified on 14th October, 2015 to monetize marginal fields of Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) and Oil India Limited (OIL) under nomination regime which remained undeveloped for a long period of time. This policy was subsequently renamed as Discovered Small Field (DSF) Policy which is now among country's flagship energy policies, in alignment with other initiatives for securing energy needs of the country.

The Government has decided to extend Discovered Small Field (DSF) Policy for fast-track monetization of un-monetized small fields / discoveries of ONGC & OIL under the nomination regime and relinquished discoveries under the PSC regime, remained un-monetized. Accordingly the DSF Policy is now being notified with the following salient features:

2. Single license for conventional and non-conventional hydrocarbons

A single license will be provided to enable E&P operators to explore and extract all hydrocarbon resources covered under the Oilfields Regulation and Development (ORD) Act, 1948, and Petroleum and Natural Gas (PNG) Rules, 1959 under one PEL/PML. This will enable the contractor to explore conventional and unconventional oil and gas resources including CBM, shale gas/oil, tight gas, gas hydrates and any other resource to be identified in future which fall within the definition of "Petroleum" and "Natural Gas" under PNG rules, 1959.

3. No restriction on exploration activity during Contract Period

The contractor will be allowed to carry out exploration activity during entire contract duration. Exploration will be at the sole risk and cost of the contractors.

4. Model for inviting the bids

Bids will be invited for the Marginal Fields on a Revenue Sharing Contract (RSC) Model. To ensure viability of operations, it is proposed to cluster fields / discoveries, as may be required at the time of Notice Inviting Offer (NIO). This revenue sharing model will be based on a revenue-based linear scale. The contractor shall be required to pay biddable Government share of revenue (net of royalty or post-royalty).

5. Ease of Doing Business

A simple and easy to administer contractual model in line with Government's efforts to promote 'Ease of Doing Business' requiring minimum regulatory burden for monetizing these fields has been developed.

6. Crude Oil Pricing and Sale

The contractor will be free to sell the crude oil exclusively in domestic market through a transparent bidding process on arms length basis. However, for the sake of calculation of Government revenue, the minimum price will be the price of Indian Basket of Crude Oil (currently comprising of Sour Grade (Oman & Dubai Average) and Sweet Grade (Brent Dated) of Crude Oil processed in Indian refineries) as calculated by Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) on a monthly basis. If the price arrived through bidding is more than the price of Indian Basket of Crude Oil then the Government's take will be calculated based on the actual price realized.

7. Natural Gas Pricing

The contractor will have freedom for pricing and allocation of gas produced from a cluster / field / discovery on arms length basis. The Government share of revenue shall be calculated as per the Domestic Natural Gas Pricing Guidelines in vogue at relevant point of time. However, if the discovered price is more than the calculation based on the Domestic Natural Gas Price Guidelines issued by the Government from time to time, then the Government's take will be calculated based on actual price realized.

8. Royalty

Royalty rates applicable under Hydrocarbon Exploration Licensing Policy (HELP) regime will be adopted in this Policy.

9. Oil Cess

No oil cess shall be applicable on crude oil / condensate production from Discovered Small Fields.

10. Customs Duty

Exemption from custom duty will be provided on all machinery, plants, equipments, materials and supplies related to petroleum operations as applicable in HELP.

11. Mining Lease

Current Mining Lease / License holder will be required to transfer/assign the Mining Lease (ML) or Petroleum Exploration License (PEL) along with all available clearances to the awardee of the area / Contractor, to the extent legally possible, or else the Contractor has to obtain the same. Lease / License rent / fees will be governed as per ORD Act 1948 and P&NG Rules 1959 as amended from time to time.

12. Contract Duration

The contract duration for development and production from the offered Discovered Small Fields would be a maximum of twenty (20) years from the effective date (effective date is the date of PEL/ML grant/ transfer /signing of deed) or till the economic life of the field as submitted by bidder along with development plan in the bid, whichever is earlier, unless the Contract is terminated earlier in accordance with its terms, but may be extended upon mutual agreement between the Parties for a further period not exceeding ten (10) years. If the production of Crude Oil or Natural Gas is expected to continue beyond the end of the relevant period referred above, the Parties may agree to extend this Contract for a further period upon such terms as may be mutually agreed. The contract can be extended based on the provisions of the contract and extant GOI guidelines, if any. Contract can be terminated earlier by GOI if the production from the offered Discovered Small Fields ceases for a period of over one (1) year at any instance.

13. Empowered Committee of Secretaries:

An Empowered Committee of Secretaries (ECS) will be constituted consisting of Secretary (Petroleum and Natural Gas), Secretary (Expenditure) and Law Secretary. Functions of ECS will include Finalizing and Approving of Model Revenue Sharing Contracts, Notice Inviting Offer (NIO) and other documents for all Discovered Small Fields Bid Rounds. ECS will conduct negotiations with the bidders, wherever necessary, and finalize and recommend the award of contracts for contract areas after successful bidding round.

14. The award of contracts will be approved by Minister of Petroleum and Natural Gas and Minister of Finance.

15. Management Committee

A Management Committee (MC) will be constituted with representatives from Government / Directorate General of Hydrocarbons (DGH) and contractor.

16. Eligibility for participation in bids

National Oil Companies, Indian companies and foreign companies either alone or in joint venture can bid for the offered Discovered Small Fields. Up to 100% participation by foreign companies, joint ventures will be allowed.

17. Site Restoration

The site restoration fund shall be maintained by the contractor, as per the notified "Site Restoration Fund Scheme-1999", as amended from time to time. The activity of site restoration will be done as per applicable rules/standards/notifications.

18. The above DSF Policy is extended to 60 identified fields / discoveries as approved by the Government. The list of identified fields / discoveries is at **Annexure**.

19. The Government has also decided to extend the above stated DSF Policy for future bidding rounds. A Committee comprising of Additional Secretary / Additional Secretary & Financial Advisor (MoPNG), JS (Exploration, MoPNG) and Director General of Hydrocarbons, will identify Fields / Discoveries to be put on offer in consultation with CMD (ONGC) and CMD (OIL) for the future bidding rounds.

20. The decision herein contained will come into force with immediate effect and will remain in force until further orders.

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Annexure

ONGC DISCOVERIES IDENTIFIED FOR DSF POLICY BID ROUND-II

S. No.	Basin Name	Discovery Details			In-place as on 01.04.2016	
		Name	Year	Type	Oil/Cond MMt	Total Gas, BCM
1	Assam Shelf	Tiphuk	2004-05	Oil + Gas	0.40	0.11
2		Tulamura	2008-09	Gas	-	0.20
3		Hazarigaon	2008-09	Gas	-	0.30
4	KG Off (SW)	GS-48-1	2007-08	Gas	-	0.42
5		G-4-6	2008-09	Oil	44.10	2.60
6		GS-69	2009-10	Oil+Gas	0.30	0.80
7		GS-KW-5	2007-08	Oil	0.13	0.41
8		GS-KW-6	2009-10	Gas	1.22	2.78
9	KG Onland	Kaza	1985-86	Gas	0.02	0.01
10		Gokarnapuram	1998-99	Gas	0.1	0.03
11		Pendurru	2001-02	Gas	-	0.12
12		Turputullu	2005-06	Gas	0.1	0.01
13		Suryaraopeta-4	2006-07	Gas	-	0.2
14	Mumbai Offshore	SD-1	1988-89	Oil+Gas	0.90	4.52
15		B-192A	1991-92	Oil	1.93	0.30
16		D-33	2004-05	Oil+Gas	23.90	16.70
17		BNP-2	2008-09	Gas	-	0.70
18		SB-15	2008-10	Oil	4.62	2.19
19		SD-1-5	2009-10	Oil+Gas	0.70	2.43
20		BH-67	2011-12	Gas	-	0.24
21	Rajasthan	Chinnewala Tibba	2007-08	Gas	-	1.90
22		Chinnewala Tibba-2	2002-04			
Total : (115.39 mtoe)					78.42	36.97

OIL DISCOVERIES IDENTIFIED FOR DSF POLICY BID ROUND-II

S. No.	Basin Name	Name	Year	Oil/Cond (MMt)	Gas (BCM)
1	Assam	South Rajgarh	1994	1.48	-
2	Assam	Madhakali	2010	0.23	-
3	Assam	Umatara	2010	3.37	-
4	Assam	Haldibari	2001	0.05	-
5	Assam	Disaijan	2009	0.98	-
Total				6.11	-

PSC REGIME DISCOVERIES IDENTIFIED FOR DSF POLICY BID ROUND-II

S. No.	Basin	Block Name	Status	Discovery Name	Discovery Year	Block Operator	Oil/Gas	Initial In-place (O+OEG), MMT
1	Cambay	CB-OS/1	PFR	GULF-A	2008-09	ONGC	Oil	4.98
2		CB-ONN-2004/2		Vadatal-10	2014-15	ONGC	Oil	0.09
3				Vadatal-11	2014-15	ONGC	Oil	0.218
4		CB-ONN-2009/5		NTPC-A1	2016-17	NTPC	Oil	8.88
5		Sanganpur		Sanganpur	2006-07	HDCPL	Oil	0.858
6		CB-ONN-2003-1		D-45	2009-10	RIL	Gas	0.008

7	Mahanadi	NEC-OSN-97/2		D-9	2004-05	RIL	Gas	5.15
8		NEC-OSN-97/2		D-10	2004-05	RIL	Gas	1.08
9		NEC-OSN-97/2		D-11	2004-05	RIL	Gas	6.48
10		NEC-OSN-97/2		D-15	2004-05	RIL	Gas	1.78
11		NEC-OSN-97/2		D-20	2005-06	RIL	Gas	0.44
12		NEC-OSN-97/2		D-21	2005-06	RIL	Gas	1.61
Total								31.57

EMAINING DISCOVERIES OF DSF BID ROUND 2016 FOR DSF POLICY BID ROUND-II

S. No.	Location Area	Field	Discovery Year	Initial In-place	
				Oil	Gas(SG+FG)
				MMt	BCM
1	Mumbai Offshore	NMT	2003-04	-	5.49
2		PER	2010-11	2.14	0.93
3		B-163	1990-91	-	0.14
4		B-14	2000-01	-	0.07
5		C-37	1994-95	-	1.33
6		C-43	1995-96	-	0.30
7		D-18	1985-86	14.78	2.06
8	Mumbai Offshore	CA	1986-87	1.93	3.51
9		SD-14	1989-90	0.05	0.04
10		CD	1986-87	-	0.07
11		ED-4	2000-01	0.03	-
12		SD-4	1988-89	0.15	0.18
13		TP	1999-00	-	0.33
14		D-12	1981-82	-	0.61
15		D-31	2000-01	3.78	0.53
16	Kutch Offshore	GK-39	2000-01	-	0.05
17	Krishna Godavari (Offshore)	GS-70	2011-12	0.4	0.45
18		YS-5	2008-09	-	1.69
19	Krishna Godavari (Onland)	Lankapalem	1995-96	-	0.22
20		Mummidivaram	1992-93	-	0.09
21		Palakollu	1986-87	-	0.23
Total (41.58 mtoe)				23.26	18.32